राष्ट्रीय संस्करण

बिल गेट्स बोले, भारत में तेज आर्थिक विकास की क्षमता
>> 12

वर्ष 3 अंक 160

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 18 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

पुनर्विचार याचिका के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष दोफाड़

बदला रुख ▶ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर, फिर से जाएंगे अदालत

पांच एकड़ भूमि लेने से भी इन्कार, कहा– 'शरीयत नहीं देता इजाजत'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष बंटा नजर आने लगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अनुचित बताते हुए नामंजूर कर दिया है। रविवार को बोर्ड की कार्यकारिणी ने अहम बैठक कर निर्णय लिया है कि कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। बोर्ड ने मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमि दूसरी जगह लेने से भी यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि यह शरीयत के खिलाफ है। हालांकि बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्णय से सहमत नहीं हैं। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी भी कह चुके हैं कि वह पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक रविवार को लखनऊ के नदवातुल उलमा में होनी थी लेकिन, प्रशासन से अनुमति न मिलने से डालीगंज स्थित मुमताज पीजी कॉलेज में हुई। बोर्ड में पचास सदस्य हैं जिसमें लगभग 35 सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित मुस्लिम नेता भी शामिल हुए।

लखनऊ में रविवार को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद जानकारी देते जफरयाब जिलानी। जागरण

करीब तीन घंटे तक चली बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तमाम बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता में बोर्ड के सचिव और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। यह महसूस किया गया है कि कोर्ट के निर्णय में कई बिंदुओं पर न केवल विरोधाभास है, बल्कि प्रथमदृष्टया अनुचित प्रतीत होता है। उनका दावा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए तीन पक्षकारों की सहमति मिल गई है। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैय्यद मोहम्मद राबे हसनी नदवी ने की। इसमें जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना वली रहमानी, जलालुद्दीन उमरी, सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, महिला सदस्य डॉ. आसमा जहरा, आमना रिजवाना, परवीन खान, ममदुहा माजिद आदि ने शिरकत की।

मस्जिद की जमीन के बदले कोई अन्य भूमि स्वीकार नहीं : जिलानी ने कहा, याचिका में इस तथ्य का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले मुस्लिम कोई अन्य भूमि स्वीकार नहीं कर सकते। मुसलमान किसी दूसरे स्थान पर अधिकार लेने के लिए कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि मस्जिद की भूमि के लिए न्याय के लिए गए थे। उन्होंने कहा, अयोध्या में नई मस्जिद बनाने की हमें क्या जरूरत है। पहले से ही वहां तमाम मस्जिदें हैं। बोर्ड के सचिव मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने कहा, शरीयत के अनुसार, हम मस्जिद के एवज में कोई वस्तु या जमीन नहीं ले सकते। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सह संयोजक कासिम रसूल इलियास बोले,हम फैसले के 30 दिन के अंदर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर देंगे।

जिलानी ने कहा,दबाव में होंगे इकबाल अंसारी : पक्षकार इकबाल अंसारी के बारे में पूछने पर जिलानी का कहना था कि पुलिस प्रशासन किसी को फैसले के खिलाफ बोलने नहीं दे रहा। हो सकता है कि अंसारी दबाव में हों।

मदनी ने बीच में छोड़ी बैठक ,कल्बे सादिक शामिल नहीं हुए : जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी बोर्ड बैठक बीच में ही छोड़ कर चले गए। दूसरी ओर बोर्ड के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना डॉ. कल्बे सादिक बैठक में शामिल नहीं हुए।

तीन पक्षकारों की मिली सहमति : जिलानी

मुस्लिम पर्सलन लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी का दावा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए तीन पक्षकारों की सहमति मिल गई है। पक्षकार जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की है। पक्षकार मौलाना महफुजर्रहमान, मो. उमर, मिसबाहुद्दीन ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

हमें नहीं चाहिए रिव्यू, जिसे कोर्ट जाना हो जाए : इकबाल

बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे मो. इकबाल अंसारी ने कहा कि हमें नहीं चाहिए रिव्यू, जिसे कोर्ट जाना हो जाए। मैं कोर्ट का फैसला स्वीकार करने के अपने रुख पर पूरी तरह से कायम हूं। दोहराया कि अब हमें बाबरी मस्जिद को भूल कर आगे की ओर देखना होगा। इकबाल उन लोगों में रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुक्तकंठ से सराहना की है और विवाद से मुक्त होकर आपसी सहमति–सौहार्द के पर्याय बनकर सामने आए हैं। बाल को सौहार्द की यह शिक्षा अपने अब्बू व बाबरी मस्जिद के मुद्दई मो. हाशिम अंसारी से विरासत में मिला है। वह अपने अब्बू की ही तरह मस्जिद की पैरोकारी के बावजूद मुस्लिमों से अधिक हिंदुओं में लोकप्रिय हैं

मामले में अब हो रही सियासत : मौलाना रजवी

बरेली : तंजीम उलमा–ए– इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि अयोध्या मामले में अब राजनीति हो रही है। अयोध्या मुद्दा खत्म हो जाने के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड इसे जिंदा रखना चाहता है। जिससे राजनीतिक बिसात सजा कर हिंदू–मुसलमान के बीच भाईचारा और देश के अमन को नुकसान पहुंचा सकें। मौलाना ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड देश के महज 25 फीसद मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। 75 फीसद मुसलमान इसके खिलाफ हैं। बेहतर होगा कि अयोध्या मामला अब यहीं छोड़ दिया जाए और उससे आगे की बात हो।

पुनर्विचार की जरूरत नहीं

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी भी कह चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वह पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जमीन लेने या न लेने के मामले में कानूनी विमर्श कर रहे हैं।

अयोध्या पर विशेष पेज
श्रीराम >> पेज 7

सरोकार

इंदौर में पराली से तैयार किए डिस्पोजेबल बर्तन

रायपुर : इंदौर जिले के एक युवा दंपती ने पराली (धान के अवशेष) से डिस्पोजेबल बर्तन तैयार किया है। इससे न सिर्फ पराली का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि होगी और कुटीर उद्योग धंधे विकसित होंगे। (पेज–11)

जागरण विशेष

किराना स्टार्टअप ने चार साल में ली 225 गुना बढ़त

इंदौर : मप्र के इंदौर जिले से संचालित होने वाला शॉप किराना स्टार्टअप धूम मचा रहा है। इसकी शुरुआत तीन दोस्तों ने 2015 में की थी। इसकी सफलता को देखते हुए अमेरिका की बैटर कैपिटल, जापान की इन्क्यूबेट फंड और नौकरी डॉट कॉम ने 14 करोड़ की फंडिंग की है। (पेज–10)

न्यूज गैलरी

राज–नीति ▶ पृष्ठ 4

झारखंड में बागी हुए सरयू राय सीएम के खिलाफ ठोकेंगे ताल

जमशेदपुर : भाजपा की टिकटों की घोषणा में वेटिंग में रखे गए झारखंड के खाद्य व आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अब पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। रविवार को जहां उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने का एलान कर दिया। वहीं, मंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

श्रीनगर–बनिहाल के बीच तीन माह बाद रेल सेवा बहाल

जम्मू : कश्मीर में बनिहाल–श्रीनगर–बारामुला रेल खंड के बीच तीन माह बाद रेल सेवा बहाल हो गई। शनिवार व रविवार को सफल ट्रायल रन के बाद रेल सेवा शुरू हो गई। राज्य प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर तीन अगस्त को सेवा बंद कर दी थी। बारामुला–श्रीनगर के बीच यह सेवा मंगलवार से ही बहाल कर दी गई थी।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

बेहतर कारोबार में जीएसटी के नियम की दीवार

वाराणसी : वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के नियम 36(4) ने व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया है। व्यापारी इस नियम के कारण जीएसटीआर–2ए में दर्ज उस माह की संपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के 20 फीसद से ज्यादा का लाभ नहीं ले पाएगा। व्यापारियों के लिए यह मुश्किल जीएसटीआर–वन भरने के समय निर्धारण में भिन्नता से है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

हांगकांग में विवि के भीतर से पुलिस पर बरसे तीर

हांगकांग : हांगकांग में रविवार को हिंसा फिर भड़क उठी। काऊलून प्रायद्वीप में अवरोधों से घिरे हांगकांग पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय से पुलिस पर तीरों और पेट्रोल बमों से हमला हुआ। विवि परिसर के बाहर बने मोर्चों की आड़ और भवन की छतों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागे व नीले रंग का तरल पदार्थ छोड़ा। हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर है।

संसद में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार : मोदी

सर्वदलीय बैठक

- प्रधानमंत्री ने पिछली बार की तरह ही यह सत्र भी सफल होने की जताई उम्मीद
- विपक्ष ने कहा, अब्दुल्ला और चिदंबरम को सत्र में भाग लेने की मिले अनुमति

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में हैं गृह मंत्री अमित शाह और अन्य दलों के नेता। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं बहस करना है। सरकार सदन के नियमों व प्रक्रियाओं के दायरे में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। रविवार को शीतकालीन सत्र की पूर्वसंध्या पर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को यह भरोसा दिलाया। वहीं विपक्ष ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कांफ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया और उन्हें सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दिए जाने की मांग की। बैठक में 27 दलों के नेताओं ने भाग लिया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के अनुसार, विपक्ष ने सत्र के दौरान आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की।

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इस सत्र के भी पिछले सत्र जितना ही फलदायी होने की उम्मीद जताई। पिछला सत्र लोकसभा के इतिहास में सबसे सफल सत्र रहा था। इस दौरान 35 विधेयक पारित हुए थे। राज्यसभा से 32 विधेयकों को स्वीकृति मिली थी। सर्वदलीय बैठक में मोदी ने कहा, संसद में रचनात्मक चर्चा नौकरशाही को भी सतर्क रखती है। विपक्षी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए पीएम ने कहा, प्रदूषण, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, किसान व कृषि समेत सभी मुद्दों पर सरकार सभी दलों के सकारात्मक सहयोग के साथ लंबित विधायी कार्यों और नीतिगत फैसलों पर काम करेगी। हालांकि विपक्ष पीएम के आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिखा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हकीकत यह है कि जब भी सदन में आर्थिक मंदी, किसानों की हालत और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, तो सरकार का रवैया बदल जाता है। विपक्ष की ओर से फारूक अब्दुल्ला को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

नेशनल कांफ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा,संसद सत्र में फारूक अब्दुल्ला की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा, 'किसी सांसद को अवैध रूप से हिरासत में कैसे लिया जा सकता है?' साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस के नेता पी. चिदंबरम को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत देने की मांग की। उनका कहना था कि पहले ऐसे मामलों में सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जा चुकी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सभी दलों की बैठक बुलाई थी और सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की थी।

सत्र हंगामेदार रहने के आसार : शीतकालीन सत्र में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, आर्थिक सुस्ती और कश्मीर जैसे मसलों पर हंगामे के आसार हैं। 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 47 बिल एवं प्रस्ताव संसद में रखे जाने हैं। सरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, ई-सिगरेट पर पाबंदी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे।

शिवसेना को विपक्ष की सीट मिली : राजग से संबंध तोड़ने के बाद शिवसेना के सांसदों के बैठने का क्रम बदल गया है। मंत्री पद छोड़ने वाले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत अब लोस में पहली के बजाय तीसरी पंक्ति में बैठेंगे। बाकी 17 सांसद भी विपक्ष के खेमे में बैठेंगे।

आज दिल्ली में बिछेगी महाराष्ट्र सरकार की बिसात

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- सोनिया गांधी से मिलकर राज्य में सरकार बनाने पर चर्चा करेंगे पवार
- कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना के बीच अब तक की बातचीत की जानकारी देंगे

सोनिया गांधी

शरद पवार (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना सरकार बनने के मामले में गेंद अब केंद्रीय नेताओं के पाले में पहुंच गई है। माना जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर सरकार बनाने के बारे में चर्चा करेंगे।

रविवार को पुणे में राकांपा की कोर कमेटी की बैठक हुई। पार्टी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राकांपा विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक के अनुसार बैठक में राज्य में चुनी हुई सरकार बनाने का निर्णय किया गया। चूंकि प्रदेश में राकांपा और कांग्रेस का चुनावपूर्व गठबंधन है, इसलिए शरद पवार सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। वे उन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना नेताओं के बीच हुई अब तक की चर्चा की जानकारी देंगे और आगे की योजना पर विचार करेंगे। उसके बाद मंगलवार को कांग्रेस-राकांपा के नेता साथ बैठकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।

महाराष्ट्र इस समय राष्ट्रपति शासन के दौर से गुजर रहा है। नौ नवंबर को पिछली विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने 105 सदस्यों वाले सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। भाजपा के असमर्थता जाहिर करने पर शिवसेना को 24 घंटे का समय दिया। शिवसेना प्रतिनिधि दी गई अवधि से 45 मिनट पहले ही राजभवन पहुंच गए थे लेकिन कांग्रेस, राकांपा के समर्थन का पत्र नहीं पहुंचने से मायूस लौटे। उसके बाद राकांपा को भी 24 घंटे का समय दिया गया, लेकिन राकांपा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। इसे सरकार बना पाने में राकांपा की असमर्थता मानते हुए राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी।

शिवसेना को सीएम पद देने को तैयार प्रदेश स्तर के नेता : शिवसेना की कांग्रेस और राकांपा नेताओं से कई स्तर पर बातचीत हो चुकी है। स्वयं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे राकांपा अध्यक्ष शरद पवार एवं कांग्रेस नेता अहमद पटेल सहित प्रदेश स्तर के नेताओं से मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि तीनों दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस और राकांपा प्रदेश स्तर के नेता शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने को राजी दिख रहे हैं। बदले में कांग्रेस और राकांपा को पूरे पांच वर्ष के लिए उपमुख्यमंत्री पद के साथ कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकते हैं।

बाला साहब ठाकरे स्मृति स्थल पर फड़नवीस के खिलाफ नारेबाजी पेज>>4

जेएनयू में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में छात्रों पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में तोड़फोड़ कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में वसंत कुंज थाने की पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में लगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही अपशब्द भी लिखे थे। इस मामले में कार्रवाई के लिए शनिवार को पुलिस को दो शिकायतें मिली थीं। अधिकारियों के मुताबिक, एक शिकायत भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने दी थी, जबकि दूसरी शिकायत स्वामी विवेकानंद स्टेच्यू स्टॉलेशन कमेटी के अध्यक्ष बुद्ध सिंह ने दी थी। इसके आधार पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात हो कि कुछ छात्रों ने गत दिवस एक टीवी चैनल की पत्रकार के साथ भी बदसुलूकी की थी। (पेज–2 भी देखें)

चीन समर्थक गोतबाया राजपक्षे होंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति

- यूएनपी के सजित प्रेमदासा को 13 लाख से अधिक वोटों से हराया
- पीएम मोदी ने भी दी बधाई, राजपक्षे बोले–मिलने को उत्सुक हूं

गोतबाया राजपक्षे फाइल फोटो

कोलंबो, प्रेट्र : पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भाई गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। चीन समर्थक माने जाने वाले राजपक्षे ने यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के प्रत्याशी सजित प्रेमदासा को 13 लाख से अधिक वोटों से हराया। राजपक्षे ने चुनावी दौरे में कई बार कहा था कि अगर वह सत्ता में आते हैं, तो चीन से रिश्तों को मजबूत बनाया जाएगा। सनद रहे कि उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका सरकार ने चीन को खूब बढ़ावा दिया। उनकी सरकार ने चीन को हंबनटोटा बंदरगाह और एयरपोर्ट का ठेका दिया। भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ से घेरने की चीन की योजना में उक्त परियोजनाएं अहम हिस्सा हैं।

गोतबाया की इस जीत के साथ ही राजपक्षे परिवार की पांच साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है। इससे पहले महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजपक्षे को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी है। जवाब में राजपक्षे ने कहा कि वह निकट भविष्य में मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। चुनाव में जीत के बाद 70 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) गोतबाया ने समर्थकों से गरिमा व अनुशासन से जीत की खुशी मनाने का आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट में कहा, 'आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका नई यात्रा की शुरुआत कर चुका है। देश का हर व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा है।'

वहीं, चुनाव में हार के बाद प्रेमदासा ने ट्वीट किया 'लोगों के निर्णय का सम्मान करना और श्रीलंका के सातवें राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने के लिए गोतबाया को बधाई देना सौभाग्य की बात है।' माना जा रहा है कि इस चुनाव परिणाम के बाद यूएनपी के नेता और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पद छोड़ सकते हैं। गोतबाया अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को नया पीएम बनाएंगे।

सिंहली बहुल इलाकों में एकतरफा जीत पेज>>13

राजपक्षे की नीतियों पर होगी भारत की नजर

नई दिल्ली : श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे पर भारत की पैनी नजर रहेगी। आतंकी संगठन लिट्टे के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान वह रक्षा सचिव थे और उन पर निर्दोष तमिल आबादी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन के काफी आरोप लगे थे। नेपाल के बाद श्रीलंका इस क्षेत्र का दूसरा देश है, जहां हुए चुनाव में किसी ऐसे व्यक्ति या पार्टी की जीत हुई है, जिसकी छवि भारत समर्थक की नहीं रही है। (पेज–13)

इस बार चुनाव मैदान में थे कुल 35 उम्मीदवार

इस राष्ट्रपति चुनाव में कुल 35 उम्मीदवार मैदान में थे। राजपक्षे को जहां 52.25 फीसद (6,924,255) वोट मिले, वहीं प्रेमदासा 41.99 फीसद (5,564,239) मत प्राप्त करने में सफल रहे। अन्य उम्मीदवारों को 5.76 फीसद वोट मिले। देश के कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए 50 फीसद या उससे अधिक मत प्राप्त करने जरूरी हैं। शनिवार को हुए मतदान में 1.59 करोड़ मतदाताओं में से 80 फीसद से कुछ ज्यादा लोगों ने भाग लिया था, यह 2015 के चुनाव से थोड़ा कम था। उस चुनाव में मैत्रिपाल सिरिसेन ने महिंदा राजपक्षे को हराया था।

सुरक्षा की चिंता

नक्सली भी कर रहे ड्रोन का इस्तेमाल

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ कैंप के आसपास तीन बार उड़ते देखे गए ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, दिखते ही मार गिराने का आदेश, भारत–पाक सीमा पर हथियारों की तस्करी में हुआ था ड्रोन का इस्तेमाल

अनिल मिश्रा, जगदलपुर

पंजाब से सटे भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद धुर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन गया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों की टोह लेने के लिए नक्सली इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में तीन बार यहां सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) कैंपों के ऊपर और आस-पास ड्रोन मंडराते देखे गए हैं।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और डीआरजी (डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड) के जवान संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। सुकमा इलाके में सीआरपीएफ ज्यादा प्रभावी है और इसी कारण यह नक्सलियों के निशाने पर है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में दो बार सीआरपीएफ के किस्टारम और पालोडी कैंप के ऊपर ड्रोन देखा गया। जवानों के मुताबिक लाल और सफेद लाइट वाले इस ड्रोन को वे गिरा पाते कि वह गायब हो गया। एक और कैंप के पास भी ड्रोन देखे जाने की चर्चा है।

प्रतीकात्मक फोटो

मामला सामने आते ही बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों को एक नई चुनौती के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बस्तर के आइजी सुंदरराज पी ने कहा कि अब तक लैंड माइंस का ही खतरा था। अब ड्रोन पर भी निगरानी रखने की रणनीति बनाई गई है। समूचे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, हालांकि अभी यह नहीं पता चल पाया है कि ड्रोन का कंट्रोल कहां था? उन्होंने कहा कि इस इलाके में आदिवासियों के पास ड्रोन के लायक संसाधन नहीं हैं। इसलिए माना जा रहा है कि नक्सली नेता सुरक्षा बलों की गतिविधियों को जानने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नक्सलियों के गढ़ में बनाया पालोडी कैंप : सीआरपीएफ ने पिछले साल ही किस्टारम से 12 किमी अंदर नक्सली मांद में घुसकर पालोडी में भी कैंप बनाया था। इससे बौखलाए नक्सलियों ने 23 मार्च 2018 को किस्टारम से पालोडी जा रहे सीआरपीएफ के वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया था जिसमें नौ जवान शहीद हुए थे।

आइजी बोले, जांच की जा रही : राज्य पुलिस के आइजी सुंदरराज ने कहा कि कैंप के ऊपर कोई अवांछित चीज उड़ेगी तो उसे शूट करने का निर्णय जवान ले सकते हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। बीते दिनों मुंबई एयरपोर्ट पर बगैर कस्टम क्लियरेंस के सौ से ज्यादा ड्रोन ले जाते एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। हालांकि उसका यहां से कोई कनेक्शन है या नहीं यह पता नहीं लग पाया है।

एनआइए कर रही जांच : पंजाब से सटे भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीते महीनों हथियारों की तस्करी में ड्रोन के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआइए) इसकी जांच कर रही है।

बेमिसाल रहा जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल

नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई रविवार को ोवानिवृत्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट में लगभग सात साल न्यायाधीश और उसमें से 13 महीने 14 दिन तक देश के प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाले जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल बेमिसाल रहा। अनुशासनप्रिय, सख्त और बेबाक व्यक्तित्व के धनी जस्टिस गोगोई ने कई ऐस फैसले दिए और काम किए जो उन्हें औरों से अलग और यादगार बनाते हैं। (पेज–3)

एलओसी के पास आइईडी धमाका, जवान शहीद

जम्मू : जम्मू जिले के सीमावर्ती अखनूर के प्लांवाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब रविवार दोपहर इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) धमाके में सेना का एक जवान शहीद और दो अन्य घायल हो गए। विस्फोट उस समय हुआ जब सेना के कुछ जवान वाहन से अग्रिम चौकी की ओर बढ़ रहे थे कि जोरदा धमाका हुआ। अस्पताल में भर्ती एक जवान की हालत गंभीर बताई जाती है। (पेज–6)

सबरीमाला मंदिर को आंदोलन का अखाड़ा नहीं बनने देंगे : केरल

- एलडीएफ सरकार के मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वत: स्टे
- सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में सभी आयु की महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं, केरल की वाममोर्चा सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार वो सबरीमाला मंदिर को आंदोलन का अखाड़ा नहीं बनने देगी।

केरल के कानून मंत्री एके बालन ने पत्रकारों से कहा, संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार अदालत के आदेश के मुताबिक ही काम कर सकती है। इस मामले में सरकार के सामने नई समस्या पैदा हो गई है। अगर यह पूछा जाय कि शीर्ष अदालत का 14 नवंबर का फैसले पहले के आदेश पर रोक है तो कानूनन इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन शीर्ष अदालत के फैसले से 28 सितंबर 2018 के आदेश पर स्वतः स्टे की तरह रोक लग गई है। दरअसल, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 14 नवंबर को तीन-दो के बहुमत से मामले को सात सदस्यीय बड़ी पीठ के सामने भेजने का फैसला किया था।

बता दें कि गत वर्ष अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने 10 से 50 आयु वर्ग समेत सभी महिलाओं के मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। इसे लेकर बहुत बवाल हुआ था। वाम मोर्चा सरकार ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश दिलाने के इंतजाम किए थे। धार्मिक रूप से प्रतिबंधित उम्र की दो महिलाओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन भी किए थे। केरल सरकार ने इस बार कहा कि वह उन महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं करेगी जो प्रचार के लिए दर्शन करने आएंगी।

तृप्ति देसाई को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी पेज>>6